an>

Title: Regarding Digital India.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय शून्य प्रहर में यहाँ उपस्थित करने की अनुमति दी, इसलिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ।

महोदया, हमारे प्रधान मंत्री जी ने और सरकार ने एक विचित्र निर्णय, एक बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया कि पूरे देश को डिजिटल इन्डिया बनायेंगे। अब उस निर्णय पर जिस ढंग से अमल होना चाहिए, पिछले बजट में 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। आप और हम सभी जानते हैं कि अगर इस देश में कोने-कोने से लेकर शहरों तक किसी की पहुँच है तो वह पहुँच बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की है।

13.00 hours

आज ये दोनों कंपनियां घाटे में हैं। इनके पास पैसे हैं, उनके पास क्षमता है। हम देख रहे हैं कि 'डिजीटल इंडिया' के लिए जो फाइबर की केबल्स डाली जा रही हैं, उसे कोई प्राइवेट कंपनी डाल रही है। इन दोनों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को उसमें शामिल करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि उस प्राइवेट कंपनी से काम न लें, पर इन कंपनियों को उसमें शामिल करेंगे तो इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी और इन्हें काम भी मिलेगा।

जैसा कि अभी हमारे एक सहयोगी सदस्य ने कहा कि वहां रोड्स हैं, पर वह मोबाइल टावर्स नहीं हैं। वहां कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगी। वे सिर्फ मुनाफा देखती हैं। सेवा का काम तो सिर्फ अपना पब्लिक सेक्टर ही करता है, जैसे 'प्रधान मंत्री जन-धन योजना' है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग कर रहा हूं कि 'डिजीटल इंडिया' के लिए यह जो ऑप्टिकल फाइबर का काम चल रहा है और इसे ग्राम पंचायतों तक जो पहुंचाने की बात है तो उसके साथ गांवों में पोस्ट ऑफिसेज़ भी हैं। इसे दोनों ज़गहों पर जाने की आवश्यकता है। हमने अभी गांवों में ग्राम पंचायत को ही प्राथमिकता दी है। पर, ये गांवों के पोस्ट ऑफिस में भी जाएं और इन दोनों सरकारी उद्यमों का भी सहयोग ले लें, इतना ही मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से है।

आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।